खबर (दार) झरोखा

भ्रष्टाचार में डूबा भारत

दुनिया के भ्रष्टाचार मुक्त देशों में शीर्ष पर गिने जाने वाले न्यूजीलैंड के एक लेखक ब्रायन ने भारत में व्यापक रूप से फैले भष्टाचार पर एक लेख लिखा है। ये लेख सोशल मीड़िया पर काफी वायरल हो रहा है। लेख की लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए विनोद कुमार ने इसे हिन्दी भाषीय पाठकों के लिए अनुवादित किया है।

भारत मे भ्रष्टाचार का एक कल्चरल पहलू है। भारतीय भ्रष्टाचार मे बिलकुल असहज नही होते, भ्रष्टाचार यहाँ बेहद व्यापक है। भारतीय भ्रष्ट व्यक्ति का विरोध करने के बजाय उसे सहन करते है। कोई भी नस्ल इतनी जन्मजात भ्रष्ट नही होती।

ये जानने के लिये कि भारतीय इतने भ्रष्ट क्यो होते हैं उनके जीवनपद्धति और परम्पराये देखिये।

भारत मे धर्म लेनेदेन वाले व्यवसाय जैसा है। भारतीय लोग भगवान को भी पैसा देते हैं इस उम्मीद मे कि वो बदले मे दूसरे के तुलना मे इन्हे वरीयता देकर फल देंगे। ये तर्क इस बात को दिमाग मे बिठाते हैं कि अयोग्य लोग को इच्छित चीज पाने के लिये कुछ देना पडता है। मंदिर चहारदीवारी के बाहर हम इसी लेनदेन को भ्रष्टाचार कहते हैं। धनी भारतीय कैश के बजाय स्वर्ण और अन्य आभूषण आदि देता है। वो अपने गिफ्ट गरीब को नही देता, भगवान को देता है। वो सोचता है कि किसी जरूरतमंद को देने से धन बरबाद होता है।

जून 2009 मे द हिंदू ने कर्नाटक मंत्री जी जनार्दन रेड्डी द्वारा स्वर्ण और हीरो के 45 करोड मूल्य के आभूषण तिरुपति को चढाने की खबर छापी थी। भारत के मंदिर इतना ज्यादा धन प्राप्त कर लेते हैं कि वो ये भी नही जानते कि इसका करे क्या। अरबो की सम्पत्ति मंदिरो मे व्यर्थ पडी है।

जब यूरोपियन इंडिया आये तो उन्होने यहाँ स्कूल बनवाये। जब भारतीय यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वो वहाँ मंदिर बनाते हैं।

भारतीयो को लगता है कि अगर भगवान कुछ देने के लिये धन चाहते हैं तो फिर वही काम करने मे कुछ कुछ गलत नही है। इसीलिये भारतीय इतनी आसानी से भ्रष्ट बन जाते हैं।

भारतीय कल्चर इसीलिये इस तरह के व्यवहार को आसानी से आत्मसात कर लेती है, क्योंकि-

1 नैतिक तौर पर इसमे कोई नैतिक दाग नही आता। एक अति भ्रष्ट नेता जयललिता दुबारा सत्ता मे आ जाती है, जो आप पश्चिमी देशो मे सोच भी नही सकते ।

2 भारतीयो की भ्रष्टाचार के प्रति संशयात्मक स्थिति इतिहास मे स्पष्ट है। भारतीय इतिहास बताता है कि कई शहर और राजधानियों को रक्षको को गेट खोलने के लिये और कमांडरो को सरेंडर करने के लिये घूस देकर जीता गया। ये सिर्फ भारत मे है।

भारतीयो के भ्रष्ट चरित्र का परिणाम है कि भारतीय उपमहाद्वीप मे बेहद सीमित युद्ध हुये। ये चकित करने वाला है कि भारतीयो ने प्राचीन यूनान और माडर्न यूरोप की तुलना मे कितने कम युद्ध लडे। नादिरशाह का तुर्को से युद्ध तो बेहद तीव्र और अंतिम सांस तक लडा गया था। भारत मे तो युद्ध की जरूरत ही नही थी, घूस देना ही सेना को रास्ते से हटाने के लिये काफी था। कोई भी आक्रमणकारी जो पैसे खर्च करना चाहे भारतीय राजा को, चाहे उसके सेना मे लाखो सैनिक हो, हटा सकता था।

प्लासी के युद्ध मे भी भारतीय सैनिको ने मुश्किल से कोई मुकाबला किया। क्लाइव ने मीर जाफर को पैसे दिये और पूरी बंगाल सेना 3000 मे सिमट गई। भारतीय किलो को जीतने मे हमेशा पैसो के लेनदेन का प्रयोग हुआ। गोलकुंडा का किला 1687 मे पीछे का गुप्त द्वार खुलवाकर जीता गया। मुगलो ने मराठो और राजपूतो को मूलत: रिश्वत से जीता श्रीनगर के राजा ने दारा के पुत्र सुलेमान को औरंगजेब को पैसे के बदले सौंप दिया। ऐसे कई केसेज हैं जहाँ भारतीयो ने सिर्फ रिश्वत के लिये बडे पैमाने पर गद्दारी की।

सवाल है कि भारतीयो मे सौदेबाजी का ऐसा कल्चर क्यो है जबकि जहाँ तमाम सभ्य देशो मे ये सौदेबाजी का कल्चर नही है?

3- भारतीय इस सिद्धांत मे विश्वास नही करते कि यदि वो सब नैतिक रूप से व्यवहार करेंगे तो सभी तरक्की करेंगे क्योंकि उनका "विश्वास/धर्म" ये शिक्षा नही देता। उनका कास्ट सिस्टम उन्हे बांटता है। वो ये हरगिज नही मानते कि हर इंसान समान है। इसकी वजह से वो आपस मे बंटे और दूसरे धर्मो मे भी गये। कई हिंदुओ ने अपना अलग धर्म चलाया जैसे सिख, जैन बुद्ध, और कई लोग इसाई और इस्लाम अपनाये। परिणामत: भारतीय एक दूसरे पर विश्वास नही करते।

भारत मे कोई भारतीय नही है, वो हिंदू ईसाई मुस्लिम आदि हैं। भारतीय भूल चुके हैं कि 1400 साल पहले वो एक ही धर्म के थे। इस बंटवारे ने एक बीमार कल्चर को जन्म दिया। ये असमानता एक भ्रष्ट समाज मे परिणित हुई, जिसमे हर भारतीय दूसरे भारतीय के विरुद्ध है, सिवाय भगवान के जो उनके विश्वास मे खुद रिश्वतखोर है।

मोदी राज के चार साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत किसी भयानक तूफान से तबाही जैसी

गिरीश मालवीय

रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों जो कन्जयूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी किया है वह बता रहा है कि मुताबिक नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त के मुकाबले इन दिनों अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी सेक्टर में बेहद निराशा की स्थिति पैदा हुई है, 2014 के मुकाबले ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है, जो यह मानते हैं कि आर्थिक स्थितियां पहले से ज्यादा खराब हुई हैं नौकरियों के मोर्चे पर भी लोगों को निराशा ही हाथ लगी है।

सरकार की तारीफ करने वाले भाजपा नेताओं की आरबीआई के आंकड़ों ने पोल खोल दी है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए सर्वे के अनुसार, देश में 48 फीसदी लोगों ने माना है कि पिछले दो सालों के मुकाबले इस साल देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है।

2015-16 में विकास दर 8.2 फीसदी थी जो 2017-18 में घटकर 6.7 फीसदी हो गई, चार वर्षों में एनपीए 2,63,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,30,000 करोड़ रुपये हो गया।

नोटबन्दी की सच्ची तस्वीर केंद्र सरकार तो नही बताएगी पर तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि 2017-18 के दौरान तमिलनाडु में 50,000 एमएसएमई इकाइयां बंद हो गईं, पांच लाख नौकरियां छिन गई। अब एक स्टेट की यह हालत है तो आप खुद सोचिए कि पूरे देश मे नोटबन्दी के बाद क्या गदर मचा होगा।

नोटबन्दी की बात निकली है तो यह बताना भी समीचीन होगा कि आरबीआई द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय जनता के पास नकदी का स्तर 19.3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। यह न सिर्फ अब तक का सबसे ज्यादा है, बल्कि नोटबंदी के बाद की स्थिति के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। जबकि नोटबंदी के 2 महीने बाद जनता के हाथ में नकदी घटकर 7.8 लाख करोड़ रुपए रह गई थी लेकिन आज इस समय चलन में कुल मुद्रा 19.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।

मई 2014 में मोदी सरकार के आने से पहले लोगों के पास लगभग 13 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा थी, एक वर्ष में यह बढ़कर 14.5 लाख करोड़ से अधिक और मई 2016 में यह 16.7 लाख करोड़ हो गई। अक्टूबर 2016 में यह 17 लाख करोड़ से अधिक हो गई।

यह आँकड़े बता रहे हैं कि जिसे नोटबन्दी के समय काला धन कहा जा रहा था वह मोदी सरकार के समय ही बहुत तेजी के साथ बढ़ा और नोटबन्दी के डेढ़ वर्षों के उपरांत फिर उसी अनुपात में आ गया। यह बात सिद्ध करती है कि नोटबन्दी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है।

जिस डिजिटल इंडिया की बात की जा रही थी, जिस कैशलेस या लेसकैश इंडिया की बात की जा रही थी वह सारी योजना रेत के महल की मानिंद धड़धड़ाते हुए गिर गयी हैं।

अर्थव्यवस्था के लिये घातक रही मोदी की नोटबंदी

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मोदी सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर तथा 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मोदी सरकार तथा भाजपा द्वारा देश भर में जश्न मनाया जा रहा है और तथाकथित उपलब्धियों का बढा-चढाकर प्रचार किया जा रहा है। लेकिन कई कारणों से सरकार की उपलब्धियां नगण्य ही हैं। स्वच्छता अभियान पर पैसा पानी की तरह बहाया गया लेकिन मोदी का यह अभियान खाली ढोल साबित हो रहा है। इसके बाद वह काला धन के नाम पर नोटबंदी लेकर आये और देश की जनता व अर्थ व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इसलिये इस नोटबंदी का विश्लेषण करना अति आवश्यक है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अचानक 8 नवम्बर 2016 को 1000 व 500 रुपये के नोटों को बंद करने व 2000 व 500 के नये नोटों के चलन की घोषणा की। मोदीजी ने नोटबंदी का लक्ष्य घोषित किया था- काले धन पर चोट, आतंकवाद की फ़ंडिंग रोकना और नकली नोटों की समस्या से छुटकारा पाना। पुराने नोटों को बदलवाने के लिये बैंकों के आगे सुबह से शाम तक लंबी-लंबी कतारें लग गई। एटीएम से पैसा निकालने के लिये लोग रात भर चक्कर लगाते रहे। काफ़ी लोगों के लिये घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया। दिहाड़ी मज़दूरों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा।

जब टेलीविज़न पर नोटबंदी से लोगों की परेशानियां नज़र आने लगी तब मोदीजी ने नोटबंदी को गरीब व अमीर के हितों के टकराव व संघर्ष में बदल दिया। मोदीजी ने टेलीविज़न पर कहा कि ये नोटबंदी अमीरो की नींद उड़ाने व ग़रीबों को चैन की नींद सोने के लिये की गई है। ग़रीब लोग अपनी परेशानियों को भुलाकर इस बात पर खुश हो गये। जब लोग बैंकों के आगे कतारों मे लगे हुये थे तो क्या किसी ने नेताओं, अधिकारियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि को उन कतारों में देखा- जवाब साफ़ है कोई नहीं। अमीर लोग़ तो चैन की नींद सोते रहे।

जल्दी ही नोटबंदी के घोषित लक्ष्य असफ़ल होते नज़र आने लगे। जैसे ही पुराने नोट वापिस बैंकों में जमा होने लगे, शुरू में तो इस अंदाज़ से खबरें दी जाती थी कि सारा काला धन पकड़ा जा रहा था, परंतु जल्दी ही सरकार को अहसास हो गया कि काला धन पकड़े जाने की सूरत नज़र नहीं आती। आरबीआई ने संसदीय पैनल को बताया कि उसे 1000 व 500 रुपये के नोट बंद से करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से मिले अघोषित धन यानी काला धन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि नोटबंदी के समय 500 और हज़ार रुपये की 15.44 लाख करोड़ रुपये की करेंसी को सिस्टम से बाहर किया गया था इसमें से 15.28 लाख करोड़ रुपये वापिस आ गये। अभी तक पता नहीं कि वह काला धन कहां है और कितना है।

आतंकवादियों के पास तलाशी में दो हज़ार वाले नये नोट मिलने लगे और देश में जगह-जगह नये नकली नोट पकड़ में आने लगे जबकि बैंकों के पास पहुंचने वाले पुराने नोटों में नकली नोटों का अनुपात ना के बराबर था।

घोषित लक्ष्य असफ़ल होते देखकर मोदी जी व सरकार ने गोलपोस्ट शिफ़्ट करने में देर नहीं लगाई। अब नकद भुगतान की जगह कैशलैश भारत का नारा दिया जाने लगा। इलैक्ट्रोनिक लेन-देन, पेटीएम आदि से भुगतान करने को बढ़ावा दिया जाने लगा और इसका प्रचार शुरू हो गया। परंतु नवीनतम खबरों के अनुसार ई-ट्रांजेक्शन का प्रचलन कम है और लोग फ़िर नकद प्रणाली की तरफ़ बढने लगे हैं। अब मोदीजी व उनके वित्तमंत्री द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि नोटबंदी के कारण कर वसूली व आयकर दाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन मोदीजी ने नोटबंदी का लक्ष्य कर वसूली व कर दाताओं की संख्या में वृद्धि करना कभी नहीं बताया था।

नोटबंदी के कारण उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सरकारी आंकड़ो के अनुसार सीमेंट उत्पादन, रिफ़ाइनरी उत्पाद, बिजली उत्पादन आदि की दर में गिरावट आई। 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी डांवाडोल हो रही है, उनमें से काफ़ी दिवालिया घोषित होने के कगार पर हैं। नोटबंदी के कारण मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सैक्टर में भी नौकरियां जा रही हैं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फर्म लार्सन एंड टुब्रो , कॉग्निजेंट, विप्रो, टेक महिंद्रा व इंफोसिस जैसी कंपनियों ने छंटनी की है। एक सर्वे के अनुसार निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर छंटनी हो सकती है।

इस आर्थिक मंदी के कारण मोदीजी की बहुप्रचारित 'मेक इन इंडिया' व 'स्टार्ट अप' योजनाओं की असफलता भी नज़र अने लगी है। 'स्टार्ट अप' लांच होने वाली संस्था में कमी आई है और कई 'स्टार्ट अप' तो बंद भी हो चुकी हैं तथा अन्य कुछ बंद होने के कगार पर हैं। असंगठित क्षेत्र में तो रोज़गार की दशा और भी दयनीय है जबकि दिहाड़ी मज़दूरों का धंधा तो लगभग चौपट हो रहा है।

नोटबंदी के कुप्रभाव से बैंकिंग क्षेत्र भी अछूता नहीं है। इसका असर बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ पर भी पड़ा है, यह घटकर 8.1 प्रतिशत पर आ गया है। क्रेडिट ग्रोथ कम होने का मतलब है कि बैंकों में पैसा तो बढा, लेकिन बैंकों से कर्ज लेने वालों की संख्या में कमी आ गई क्योंकि लोग बैंकों से कर्ज़ तब लेंगे जब उन्हें कहीं निवेश करने से मुनाफ़ा होता नज़र आये। लेन-देन की रफ़्तार कम होने से बैंकों की आमदनी भी कम होगी। एक्सपर्ट्स और बैंकर्स का कहना है कि यह बैंकों की वित्तीय सेहत के लिये अच्छा नहीं है। उनके अनुसार बैंक जितना कर्ज़ देंगे, कमाई उतनी ज़्यादा होगी।

नोटबंदी प्रकरण में कोबरा पोस्ट की स्टिंग रिपोर्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल बैंकिंग कंपनी पेटीएम के संघ परिवार से घनिष्ठ संबंध है और मोदी सरकार के हर मूव (नोटबंदी समेत) की पेटीएम को पहले से खबर थी।

परिणामस्वरूप मोदी का नोटबंदी जैसा डिजास्टर स्ट्रोक पेटीएम के लिये जीवनदायी साबित हुआ। साफ़ जाहिर है कि मोदी सरकार ने नोटबंदी का निर्णय अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिये लिया, परंतु देश की अर्थव्यवस्था को संकट के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया।

मोदीराज का सबसे बड़ा घोटाला.....

देश के सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने सिर्फ 2017-18 के वित्त वर्ष में ही 1,44,093 करोड़ रुपये के लोन को बट्टे खाते (राइट ऑफ) में डाल दिया। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2016-17 के मुकाबले 61.8 फीसद ज्यादा है, 2016-17 में 89 हजार करोड़ से अधिक के लोन को राइट ऑफ किया गया था, इस सबके बावजूद वित्त वर्ष 2018 में एनपीए 10.3 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है

आरबीआई के पूर्व डि?टी गवर्नर केसी. चक्रवर्ती ने बैंक लोन को बट्टे खाते में डालने को सबसे बड़ा घोटाला कहा है, 'टेक्निकल राइट-ऑफ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह अपारदर्शी है और इसे बिना किसी नीति के अंजाम दिया जाता है। आमतौर पर संकट के समय में अच्छी तरह से समझ-बूझकर छोटी-मोटी राशि को बट्टे खाते में डाला जाता है। लोन को तकनीकी आधार पर ठंडे बस्ते में डालने से अपारदर्शिता पैदा होती है। साथ ही क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का पूरा तानाबाना भी तबाह हो जाता है और बैंकिंग प्रणाली में तमाम तरह की गलत चीजें भी आने लगती हैं। यह जरूरी तौर पर बताना चाहिए कि लोन की कितनी राशि को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, क्योंकि आप जनता के पैसे को बट्टे खाते में डाल रहे होते हैं। यह एक घोटाला है।